निजी बैंकों की नजर बड़े गोल्ड लोन पर

▶ बड़े कर्ज वाले ग्राहकों पर निजी बैंकों का फोकस

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नयी दिल्ली, 6 सितंबर गोल्ड लोन यानी सोने के बदले कर्ज देने के कारोबार में बड़े प्राइवेट बैंकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है. मजबूत ग्रोथ, आकर्षक रिटर्न और ग्राहकों के बीच बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए बड़े निजी खास रकम बैंक खास तौर पर ज्यादा कमार वाहन सेदारी बढ़ाने की तैयारी में हैं.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, संगठित गोल्ड लोन बाजार में प्राइवेट बैंकों की मौजूदगी पहले सीमित रही है. इसकी बड़ी वजह इस कारोबार को शुरू करने के लिए होने वाला शुरुआती निवेश है. गोल्ड लोन कारोबार के लिए विशेष शाखाएं, प्रशिक्षित गोल्ड वैल्यूअर, सुरक्षित वॉल्ट और अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है. इसके चलते दूसरे रिटेल लोन प्रोडक्ट्स की तुलना में इस कारोबार में निवेश की भरपाई होने में ज्यादा समय लगता है. गोल्ड लोन एनबीएफसी और सरकारी बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में मजबूत नेटवर्क का फायदा मिलता है. इन संस्थानों के पास व्यापक ब्रांच नेटवर्क, तेज लोन प्रोसेसिंग, आसान दस्तावेजी प्रक्रिया और स्थानीय ग्राहकों के साथ पुराने संबंध हैं.

28% सीएजीआर से बढ़ेगा गोल्ड लोन बाजार

मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 से वित्त वर्ष 28 के बीच भारत का कुल गोल्ड लोन उद्योग करीब 28% सीएजीआर की दर से बढ़ सकता है. इस दौरान बड़े प्राइवेट बैंकों और डायवर्सिफाइड एनबीएफसी की बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में गोल्ड लोन बाजार में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है. खासकर शहरी इलाकों और बड़े रकम वाले कर्ज में प्राइवेट बैंकों की मौजूदगी बढ़ने की संभावना है, जबकि ग्रामीण और छोटे टिकट वाले लोन में गोल्ड लोन एनबीएफसी की पकड़ मजबूत रह सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार एनबीएफसी ऐसे ग्राहकों को भी लोन उपलब्ध कराते हैं जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था के सामान्य क्रेडिट मानकों पर खरे नहीं उतर पाते. हालांकि, गोल्ड लोन कारोबार में तेज वृद्धि, बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न, कम क्रेडिट लागत और ग्राहकों की बढ़ती स्वीकार्यता ने बड़े प्राइवेट बैंकों को इस सेगमेंट में विस्तार के लिए प्रेरित किया है.बड़े निजी बैंक अब गोल्ड लोन कारोबार के लिए अलग शाखाएं, विशेषज्ञ टीम, डिजिटल सोर्सिंग और ऑटोमेशन जैसी सुविधाओं पर निवेश बढ़ा रहे हैं.

एफएमसीजी सेक्टर पर बढ़ा ईएसजी खतरा

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

मुंबई, 6 सितंबर, भारत के करीब 245 अरब डॉलर के एफएमसीजी सेक्टर के लिए पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) से जुड़े जोखिमों और अवसरों का आकलन करने के लिए नया फ्रेमवर्क जारी किया गया है. एस्पायर सर्कल और एस्पायर इम्पैक्ट ने इम्पैक्ट फ्यूचर प्रोजेक्ट के तहत एफएमसीजी एन ईएसजी परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क नाम से यह रिपोर्ट जारी की है.

इस पहल में ईएसजी, सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस से जुड़े 19 वरिष्ठ विशेषज्ञों ने योगदान दिया है. इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य एफएमसीजी कंपनियों के ईएसजी प्रदर्शन को मापने के साथ-साथ उनके सामने मौजूद जोखिमों और टिकाऊ विकास के अवसरों की अलग-अलग पहचान करना है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के एफएमसीजी सेक्टर ने 2024 में करीब 245.4 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया.

1.4 अरब से ज्यादा लोगों तक सीधी पहुंच

पैकेजिंग कचरा और जल संकट बड़ी चुनौती

इसके वित्त वर्ष 2027 तक बढ़कर 615.9 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है. यह सेक्टर देश की 1.4 अरब से अधिक आबादी तक सीधे पहुंचता है.

फ्रेमवर्क में एफएमसीजी कंपनियों के लिए कई प्रमुख ईएसजी जोखिमों की पहचान की गई है. इनमें पैकेजिंग कचरा, पानी की कमी, ऊर्जा की ज्यादा खपत, सप्लाई चेन की ट्रेसबिलिटी, टिकाऊ सोर्सिंग, उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा, जिम्मेदार मार्केटिंग और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है. एफएमसीजी कंपनियों के लिए पैकेजिंग खास चुनौती है, क्योंकि रोजमर्रा की बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग से भारी मात्रा में कचरा पैदा होता है. वहीं, पानी की उपलब्धता और जल-संकट भी मैन्युफैक्चरिंग तथा सप्लाई चेन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम बनता जा रहा है.

क्रूड उछला, पेट्रोल-डीजल के दाम हुए स्थिर

▶ कच्चा तेल 96 डॉलर प्रति बैरल पार

▶ भारत में आज भी ईंधन के दाम स्थिर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 6 सितंबर पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है.

कारोबारी सत्र के बाद ब्रेंट क्रूड करीब 96.28 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई भी 91 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहा. होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर हमलों और आपूर्ति बाधित होने की आशंका ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में इस तेज उछाल का असर फिलहाल भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा है. सरकारी तेल कंपनियों ने 6 सितंबर 2026 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.

एफपीआई ने सितंबर के पहले सप्ताह में निकाले 10,289 करोड़ रुपये

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

मुंबई, 06 सितंबर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार में 10,289 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की. शुद्ध बिकवाली बाजार में लगाई गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है.

तीन महीने लगातार पूंजी लगाने के बाद एफपीआई बाजार में बिकवाल दिखे हैं. इससे पहले अगस्त में उन्होंने 25,492 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था. जुलाई में उन्होंने 40,031 करोड़ रुपये और जून में 4,669 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था.

सितंबर में अबतक एफपीआई ने इक्विटी में 7,443 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है.

हैदराबाद में टीसीएस बनाएगी एआई सेंटर

▶ 264 एकड़ में बनेगा एक गीगावाट डेटा सेंटर

▶ टीसीएस और साझेदार करेंगे 70 हजार करोड़

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

हैदराबाद, 6 सितंबर टाटा समूह की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टीसीएस हैदराबाद में 264 एकड़ में एक गीगावाट का डेटा सेंटर स्थापित करेगी।कंपनी ने बताया कि वह अपनी सहायक कंपनी हाइपरवॉल्ट एआई डेटा सेंटर लिमिटेड के जरिये यह डेटा सेंटर शुरू करेगी। इसके लिए उसने जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है.

टीसीएस हाइपरवॉल्ट को चरणबद्ध तरीके से विकसित कर रही है. वह हाइपरस्केलर्स, एआई कंपनियों और वैश्विक कंपनियों के लिए सुरक्षित, विस्तार के विकल्प के साथ और एआई-रेडी डेटा सेंटर अवसंरचना तैयार कर रही है. हाइपरवॉल्ट के डेटा सेंटर विशेष रूप से एआई वर्कलोड के लिए बनाये जा रहे हैं. इनमें लिक्विड कूलिंग, डायरेक्ट टू चिप कूलिंग, हाई रैक डेनसिटी, हरित ऊर्जा और विश्वसनीयता को जोड़ने वाला एनर्जी मॉडल तथा मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी. कंपनी और उसके साझेदार इस अवसंरचना के निर्माण और प्रबंधन के लिए 70,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं.

हरित ऊर्जा और जल-निरपेक्ष डिजाइन के सिद्धांतों का इस्तेमाल होगा

टीसीएस ने बताया कि हैदराबाद का यह एआई डेटा सेंटर कैम्पस विशेष रूप से फ्रंटियर एआई कंपनियों और हाइपरस्केलर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जायेगा. इसमें एआई प्रशिक्षण, इंफ्रेंस और आधुनिक कंप्यूटिंग वर्कलोड्स के लिए हाई-डेंसिटी जीपीयू लगाने की सुविधा होगी.पूरी तरह विकसित होने के बाद इस परिसर के देश के सबसे उन्नत और सबसे बड़े एआई अवसंरचना परिसरों में शामिल होने की उम्मीद है. परिसर के निर्माण में हरित ऊर्जा और जल-निरपेक्ष डिजाइन के सिद्धांतों का भी इस्तेमाल किया जायेगा.

एलआईसी को आईसीआईसीआई बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी

▶ आईसीआईसीआई बैंक में 4.35% हिस्सेदारी

▶ आरबीआई ने एक साल की दी समयसीमा

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

मुंबई, 06 सितंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम को निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99 प्रतिशत करने की अनुमति प्रदान कर दी है.

आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे 04 सितंबर की रात आरबीआई से एलआईसी के नाम जारी पत्र की प्रति प्राप्त हुई है. इसमें बताया गया है कि केंद्रीय बैंक ने एलआईसी के आवेदन पर विचार के बाद उसे एक साल के भीतर बैंक में अपनी कुल हिस्सेदारी 9.99 प्रतिशत तक करने की अनुमति दे दी है. एक साल के भीतर ऐसा न कर पाने की स्थिति में यह अनुमति अपने-आप रद्द मानी जायेगी. यह अनुमति कतिपय नियामकीय अर्हताओं को पूरा करने की शर्त के साथ प्रदान की गयी है. उल्लेखनीय है कि 30 जून की शेयरधारिता के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी 4.35 प्रतिशत है. आरबीआई की अनुमति से बाद जीवन बीमा कंपनी 5.64 प्रतिशत तक अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदकर उसे 9.99 प्रतिशत तक पहुंचा सकेगी.

वेकोलि में स्वच्छता अभियान की तैयारियों की समीक्षा

नवभारत कनेक्ट

नागपुर, 6 सितम्बर. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) ने विशेष अभियान 6.0 एवं 'स्वच्छता ही सेवा' 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा हेतु, 5 सितंबर, 2026 को वेकोलि के निदेशक (कार्मिक)/(वित्त) श्री बिक्रम घोष की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में वेकोलि मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित महाप्रबंधक (सिविल-वेलफेयर), महाप्रबंधक (एमएम-स्टोर्स), महाप्रबंधक (सिस्टम्स) एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (वेकोलि) उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक, स्टाफ अधिकारी (सिविल, सिस्टम्स एवं एमएम) तथा नोडल अधिकारी (वेलफेयर एवं सीएसआर) भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

बैठक में अभियान के प्रमुख केंद्र-बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इनमें ई-वेस्ट प्रबंधन, लंबित मामलों का निपटारा, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्थान का अनुकूलतम उपयोग, डिजिटलीकरण तथा कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर स्पष्ट एवं दृश्यमान स्वच्छता परिणाम प्रमुख रहे। बैठक में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की 'वेस्ट टू वेल्थ' पहल तथा कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित ई-वेस्ट प्रबंधन थीम पर विशेष जोर दिया गया।

धूत ट्रांसमिशन ने आईपीओ निवेशकों को दिया 85% रिटर्न

नवभारत न्यूज नेटवर्क

मुंबई, 6 सितम्बर वायरिंग हार्नेस और इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने वाली प्रमुख कंपनी धूत ट्रांसमिशन लिमिटेड के आईपीओ ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के आईपीओ को आए महज एक माह में ही निवेशकों को करीब 85 फीसदी का जबरदस्त रिटर्न मिल चुका है।

41 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दोपहिया और तिपहिया वायरिंग हार्नेस बाजार में अग्रणी धूत ट्रांसमिशन का आईपीओ पिछले माह आया था। कंपनी ने आईपीओ में शेयर का मूल्य 871 रुपये प्रति शेयर रखा था। महाराष्ट्र स्थित तीन दशक पुरानी कंपनी के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर वृद्धि संभावनाओं के कारण आईपीओ को निवेशकों का जोरदार समर्थन मिला था और इसे 74 गुना सब्सक्राइब किया गया। कंपनी के शेयर ने 17 अगस्त को आईपीओ मूल्य 871 रुपये की तुलना में करीब 38 फीसदी प्रीमियम के साथ 1200 रुपये पर सूचीबद्ध होकर निवेशकों को शुरुआत में ही अच्छा रिटर्न दिया।

अडानी डिफेंस का एके-203 समझौता

आईआरआरपीएल से पांच साल का करार

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नयी दिल्ली, 06 सितंबर अडानी डिफेन्स एंड एयरोस्पेस ने इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लि के साथ गोली-बारूद की आपूर्ति के लिए पांच वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.

आईआरआरपीएल भारत-रूस संयुक्त उपक्रम है, जो भारत में एके-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण करता है.अडानी डिफेन्स एंड एयरोस्पेस इन राइफलों के लिए 7.62गुना 39 मिमी छोटे-कैलिबर के गोली-बारूद का विनिर्माण एवं आपूर्ति करेगी. कंपनी ने भारत में स्मॉल-कैलिबर गोला-बारूद के निर्माण की क्षमताएं स्थापित की हैं, जिसमें कानपुर स्थित एक फैक्ट्री भी शामिल है जहां छोटे-कैलिबर के गोले-बारूद बनाए जाते हैं.

कंपनी ने कहा है कि यह समझौता छोटे हथियारों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को और मजबूत करने वाला है तथा इससे रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर-भारत के प्रयासों में मदद मिलेगी. आईआर आरपीएल की स्थापना वर्ष 2019 में भारत-रूस अंतर-सरकारी समझौते के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एके-203 असॉल्ट राइफलों के स्वदेशी निर्माण के उद्देश्य से की गई थी.

समाचार विशेष

महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के संकेत

यूबीटी के 14 विधायक शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल, नेता का दावा

मुंबई, 6 सितंबर. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर संभावित बड़े सियासी उलटफेर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. शिवसेना के शिंदे गुट के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना यूबीटी के 14 विधायक आगामी नवरात्रि से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.

हालांकि, शिंदे गुट की ओर से किए गए इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. न ही फिलहाल उद्धव गुट के किसी विधायक की ओर से इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा सामने आई है.महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट के पास फिलहाल 20 विधायक हैं. ऐसे में अगर 14 विधायकों के शिंदे गुट में जाने का दावा सही साबित होता है, तो यह शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा. इसी वजह से अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिंदे गुट में शामिल होने का दावा किए जा रहे ये 14 विधायक आखिर कौन हैं. शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता के दावे के मुताबिक, इन विधायकों को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी तीन मंत्रियों को सौंपी गई है. हालांकि, इन मंत्रियों के नाम या कथित तौर पर संपर्क में आए विधायकों की आधिकारिक सूची फिलहाल सामने नहीं आई है. दावे के मुताबिक, आगामी नवरात्रि से पहले इस संबंध में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो सकता है. यदि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान को नया मोड़ मिल सकता है.

फिर चर्चा में शिवसेना के दोनों गुट

शिवसेना में विभाजन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों गुटों के बीच लगातार राजनीतिक और कानूनी संघर्ष देखने को मिला है. ऐसे में यूबीटी के 14 विधायकों के शिंदे गुट में जाने का यह दावा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या यह दावा महज राजनीतिक बयान साबित होता है या आने वाले दिनों में वास्तव में कोई बड़ा दलबदल देखने को मिलता है.

केरल में सीपीएम बनाम सीपीआई

तिरुवनंतपुरम, 6 सितंबर. केरल में लगातार 10 साल राज करने के बाद लेफ्ट मोर्चा सत्ता से बाहर हुआ है और सत्ता से बाहर होते ही मोर्चे की पार्टियों में खींचतान शुरू हो गई है.

वैसे सीपीएम और सीपीआई के बीच पहले से तनातनी रहती है और कई बातों पर सरकार में रहते भी मतभेद रहे थे. जैसे सीपीएम नेता पिनराई विजयन की सरकार ने केंद्र सरकार का फंड हासिल करने के लिए स्कूलों लागू होने वाली पीएमश्री योजना को लागू करना चाहा था लेकिन सीपीआई के विरोध के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा था. विपक्ष में आने के बाद दोनों में वैचारिक और अन्य मुद्दों पर संघर्ष तेज हो गया है. दोनों के बीच विवाद का ताजा मामला विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष का पद है. नेता प्रतिपक्ष का पद पहले ही सीपीएम को मिल गया है. पूर्व मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. अब उप नेता प्रतिपक्ष पद पर भी सीपीएम ने ही दावा किया है. दूसरी ओर सीपीआई का कहना है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर चलना चाहिए. नेता प्रतिपक्ष का पद अगर सीपीएम ने लिया है तो उप नेता प्रतिपक्ष का पद सीपीआई को मिलना चाहिए.

आकाश के करियर पर फिर छाए बादल

लखनऊ, 6 सितंबर. भारतीय राजनीति में वंशवाद को लेकर काफी चर्चा होती रहती है मगर अपने यहां कई तरह का वंशवाद है जैसे पिता या माता से बेटा या बेटी को सत्ता मिलती है या उन्हें राजनीति में फायदा पहुंचता है. लेकिन भारतीय राजनीति में अपको बेटों के अलावा भतीजों का भी खूब जिक्र मिलेगा जो किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं.

अभी सबसे अधिक चर्चा में हैं आकाश आनंद, जी हां ये मायावती के भतीजे हैं और बार बार कहा जाता है कि आकाश आनंद ही मायावती के असली उत्तराधिकारी हैं. मगर मायावती ने उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुलाई बैठक के बाद यह एलान कर दिया कि आकाश अभी अपरिपक्व हैं और इस चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी.

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को पार्टी की आल इंडिया बैठक में पिछले दिये गये कार्यों की समीक्षा व उनकी कमियों को दूर करने के निर्देश दिए. साथ ही, हर वर्ष के सालाना होने वाली गतिविधियों के बारे में भी पार्टी के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों को दिये गये जरूरी दिशा-निर्देशों का पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अनुपालन करने की भी सख्त हिदायत दी. इस दौरान मायावती ने कहा कि कांशीराम ने अपने मां-बाप का घर, परिवार, रिश्तों-नातों को छोड़कर और अपना सब कुछ त्यागकर पूरा जीवन कड़ा संघर्ष करते रहे और मुझे भी खासकर शोषितों को जागरुक करने के लिए देश के कोने-कोने में भेजकर इस योग्य बनाया कि मैं उन्हीं के नक्शेकदम पर चलते हुए उनके अधूरे रहे कारवां को आगे बढ़ाने की पूरी त्याग व तपस्या में लगी रहूं. अन्ततः उन्होंने मुझे बहुजन मूवमेंट का राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बनाया.

जो भी बसपा व बहुजनों के हित के काम करेगा उसका स्वागत व आभार भी है.

विशेष | महिला आरक्षण बिल में संशोधन कराएं और यह काम होने से पहले मंत्रिपरिषद में फेरबदल करें तो उससे बहुमत जुटाने का प्रयास अलग प्रभावित होगा

नई दिल्ली, 6 सितंबर. भाजपा कैच 22 सिचुएशन में फंस गई है. उसके सामने दुविधा है कि पहले विशेष सत्र बुला कर महिला आरक्षण बिल में संशोधन कराएं और परिसीमन बिल पास कराएं या मंत्रिपरिषद में फेरबदल करें. संसद में दो तिहाई

भाजपा कैच 22 सिचुएशन में फंसी

बहुमत नहीं हो रहा है कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन कराएं और यह काम होने से पहले मंत्रिपरिषद में फेरबदल करें तो उससे बहुमत जुटाने का प्रयास अलग प्रभावित होगा.

सो, सरकार और भाजपा दोनों दुविधा में हैं. पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज हुई है कि संसद का विशेष सत्र बुला कर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराना है. वैसे एक देश, एक चुनाव के लिए लाए गए 129वें संविधान संशोधन पर भी चर्चा तेज हो गई है और इस पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख पीपी चौधरी की ओर से इसे 2029 के चुनाव में ही लागू करने के संकेत दिए जा रहे हैं. फिर भी सरकार इसके लिए इंतजार करेगी. इसके लिए विशेष सत्र नहीं होगा.

अब सवाल है कि संसद का विशेष सत्र कब होगा? ध्यान रहे अभी तक मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है. संसद के दोनों सदन 13 अगस्त को अनिश्चितकाल तक स्थगित हुए थे लेकिन अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है. इसका अर्थ है कि सरकार जब चाहे तब सत्र बुला सकती है. उसे राष्ट्रपति से मंजूरी लेने की जरुरत नहीं है. भाजपा की ओर से बताया जा रहा है कि पहले भी कांग्रेस की सरकारें ढाई महीने तक संसद का सत्रावसान नहीं करने की मिसाल है. हालांकि विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा यह इस बात पर निर्भर है कि सरकार दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटा पा रही है या नहीं. अगर एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर दे तो सरकार का आंकड़ा पूरा हो जाएगा. लेकिन ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के सत्तारूढ़ टीवीके और कांग्रेस की ओर से विधानसभा से पास कराए गए परिसीमन विरोधी प्रस्ताव के कारण डीएमके बैकफुट पर है. उसकी सहमति का इंतजार हो रहा है. उसके बाद ही विशेष सत्र का फैसला होगा. फिर भी कहा जा रहा है कि सितंबर में सरकार यह काम करने का प्रयास करेगी.

...तो मंत्रिपरिषद विस्तार टलता रहेगा

सितंबर में कैबिनेट में फेरबदल की भी चर्चा है. लेकिन कहा जा रहा है कि यह काम महिला आरक्षण बिल में संशोधन और परिसीमन बिल पास होने के बाद ही किया जाएगा. जानकार सूत्रों का कहना है कि भाजपा की ओर से सभी पार्टियों के सामने मंत्री पद का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि डीएमके समर्थन देगी भी तो सरकार में शायद ही शामिल हो. लेकिन उसके अलावा ममता बनर्जी की पार्टी से अलग हुए सांसद हों या उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़ने वाले सांसद हों या शरद पवार की एनसीपी हो सबके सामने मंत्री पद का लालच है.

जेन-जी की समस्याओं को दूर करना जरूरी

साथ ही, वर्तमान में जेन-जी व जेन-अल्फा आदि की भी चल रही गंभीर समस्याओं को दूर करना बहुत जरूरी है. राज्यों के साथ-साथ खासकर केंद्र सरकार भी इन सब मामलों को जरूर गंभीरता से ले, तो यह देश व जनहित में उचित होगा. मायावती ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और पंजाब में सभी कार्य चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही पूरा करने के भी जरुरी निर्देश दिए. इसके तहत उन्होंने 25 अगस्त को पंजाब और 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश की अलग से पार्टी की बड़ी बैठक भी बुलाई थी.